झारखण्ड सरकार

श्री रघुवर दास
माननीय मुख्यमंत्री

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

वार्षिक कार्य प्रतिवेदन 2015-2016
वार्षिक कार्य योजना 2016-2017

झारखण्ड सरकार
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग

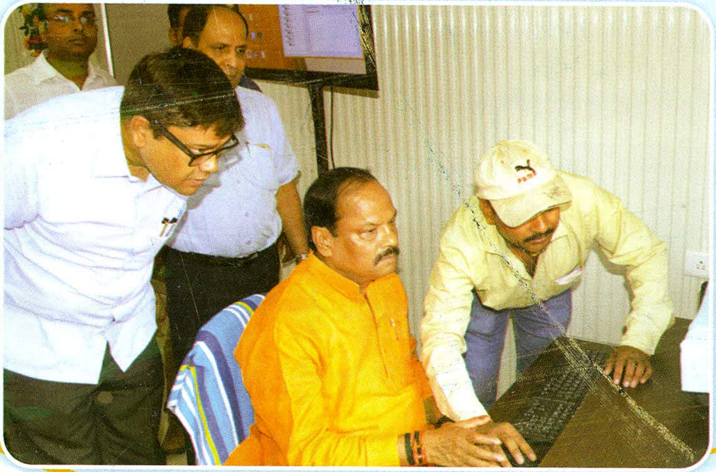

झारखण्ड सरकार

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

वार्षिक कार्य प्रतिवेदन
2015-16

एवं

वार्षिक कार्य योजना
2016-17

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

राज्य की जनता को सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों एवं योजनाओं से विभिन्न संचार माध्यमों के जरिए अवगत कराना तथा जनता की समस्याओं एवं क्रिया–प्रतिक्रिया से सरकार को अवगत कराना सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग का मुख्य दायित्व है। राज्य की कल्याणकारी योजनाओं को संचार के विभिन्न माध्यमों यथा प्रेस, प्रकाशन, प्रदर्शनी, होर्डिंग, विज्ञापन आदि के साथ–साथ न्यू एज मीडिया के माध्यम से विस्तृत प्रचार–प्रसार किया जाता है। विभाग के द्वारा स्थानीय फिल्मकारों को प्रोत्साहित करने एवं पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा देने के उद्देश्य से झारखण्ड फिल्म नीति 2015 का गठन किया गया है। वस्तुतः यह विभाग सरकार एवं जनता के बीच सेतु का कार्य करता है। यह सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों के संबंध में सूचना उपलब्ध कराकर जनजागरुकता उत्पन्न करता है तथा कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन एवं पुनर्गठन हेतु फीडबैक प्राप्त करता है।

वर्ष 2015–16 में विभाग की प्रमुख उपलब्धियाँ

1. राज्य के पत्रकारों/मीडिया कर्मियों के कल्याणार्थ प्रेस क्लब का निर्माण कार्य रांची में प्रारम्भ किया गया है जो वित्तीय वर्ष 2017–18 में पूर्ण हो जायेगा। इसके अतिरिक्त अगले वित्तीय वर्ष में धनबाद एवं देवघर में प्रेस क्लब का निर्माण किया जायेगा।

2. स्थानीय फिल्मकारों को प्रोत्साहित करने एवं पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा देने के उद्देश्य से फिल्म नीति का गठन किया गया है, जिसका सीधा लाभ स्थानीय कलाकारों को मिलेगा तथा राज्य में फिल्म उद्योग की स्थापना भी सार्थक होगी।

3. सरकार के द्वारा झारखण्ड विज्ञापन नियमावली 2015 का गठन किया गया है, जिसके द्वारा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के वर्गीकृत विज्ञापनों, निविदा सूचना, उपलब्धियों तथा अन्य सामग्रियों को विज्ञापन के रूप में प्रकाशित करने तथा केन्द्रीकृत भुगतान एवं अनुश्रवण करने में आसानी होगी।

4. सरकार के द्वारा 28 एल.ई.डी. स्क्रीन वैन के माध्यम से सरकार की नीतियों/योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुँचाने की शुरुआत की गई है।

5. सरकार के द्वारा जन संवाद के माध्यम से लोगों की समस्याओं का निदान किया जा रहा है एवं सरकारी नीतियों को आम लोगों तक उपलब्ध कराया जा रहा है।

6. ईटखोरी महोत्सव– 2016 को राजकीय महोत्सव का दर्जा प्राप्त हुआ है। विभाग के द्वारा इस महोत्सव में व्यापक पैमाने पर सरकार की नीतियों/कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार किया गया।

7. विभाग द्वारा e-gov. के सिद्धातों को अपनाते हुए राज्य सरकार के सभी प्रकार के विज्ञापनों की ऑनलाइन प्राप्ति से लेकर भुगतान तक का कार्य किया जा रहा है, जिसके कारण अब कर्मियों को विज्ञापन लेकर राँची नहीं आना पड़ता है, जिससे राजस्व की बचत हो रही है, वहीं समाचार पत्रों को भी विभाग में विज्ञापन लेने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता है।

8. जिला जन–सम्पर्क कार्यालयों द्वारा पारंपरिक संचार माध्यमों से गीत–नाट्य योजना के तहत् स्थानीय लोक कलाकारों की मंडली द्वारा राज्य की विकास योजनाओं एवं अन्य विषयों पर प्रचार–प्रसार किया गया।

9. राज्य एवं जिला स्तर पर आयोजित विभिन्न मेलों में विभाग द्वारा प्रदर्शनी–सह सूचना शिविर लगाये गये। इस प्रकार के शिविर देवघर एवं बासुकिनाथ के श्रावणी मेला, दुमका के हिजला मेला, राँची में रथ यात्रा, सरस मेला एवं मुड़मा मेला, इटखोरी महोत्सव इत्यादि के अवसर पर आयोजित किये गये।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

वित्तीय वर्ष 2015–16 में गैर योजना मद में बजट उपबंध

वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए गैर–योजना में मुख्य शीर्ष 2251 सचिवालय सेवाएँ तथा 2220 सूचना तथा प्रचार के अंतर्गत क्रमशः 76,08,000 / – तथा 78,12,80,000 / – रुपये का उपबंध निम्न प्रकार हैः–

क्रम सं०	मुख्यशीर्ष / लघुशीर्ष / उपशीर्ष	बजट उपबंध (रुपये)
1.	2251– सचिवालय सामाजिक सेवाएँ–090– सचिवालय–15– सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग	76,08,000
2.	2220– सूचना तथा प्रचार–01– फिल्म –001 निदेशन और प्रशासन –01– निदेशन एवं प्रशासन	8,18,69,000
3.	2220– सूचना तथा प्रचार–01– फिल्म –001 निदेशन और प्रशासन –02– पत्रकार कल्याण कोष	15,00,000
4.	101– विज्ञापन और दृश्य प्रचार–02– सरकारी विज्ञापन	55,00,00,000
5.	106– क्षेत्र प्रचार –02– जिला भ्रमणशील इकाइयाँ	14,79,11,000
	कुल	**78,88,88,000**

गैर योजना मद में 2016–17 मे प्रस्तावित बजट

वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए गैर–योजना में मुख्य शीर्ष 2251 सचिवालय सेवाएँ तथा 2220 सूचना तथा प्रचार के अंतर्गत क्रमशः 84,01,000 / – तथा 53,79,47,000 / – रुपये का उपबंध निम्न प्रकार किया गया हैः–

क्रम सं०	मुख्यशीर्ष / लघुशीर्ष / उपशीर्ष	बजट उपबंध (रुपये)
1.	2251– सचिवालय सामाजिक सेवाएँ–090– सचिवालय–15– सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग	84,01,000
2.	2220– सूचना तथा प्रचार–01– फिल्म –001 निदेशन और प्रशासन –01– निदेशन एवं प्रशासन	7,52,99,000
3.	2220– सूचना तथा प्रचार–01– फिल्म –001 निदेशन और प्रशासन –02– पत्रकार कल्याण कोष	15,00,000
4.	101– विज्ञापन और दृश्य प्रचार–02– सरकारी विज्ञापन	35,00,00,000
5.	106– क्षेत्र प्रचार –02– जिला भ्रमणशील इकाइयाँ	11,11,48,000
	कुल	**54,63,48,000**

वित्तीय वर्ष – 2015-16 में योजना मद में प्राप्त बजट उपबंध

चालू योजना

योजना उद्व्यय 3400 लाख

(रुपये लाख में)

क्र० सं०	योजना का नाम	कुल बजट उपबंध	जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना	अन्य क्षेत्रीय उपयोजना
1	फ्लैक्स, होर्डिंग, पुस्तिका (पम्पलेट्स) का निर्माण एवं प्रकाशन तथा साहित्य, मैगजीन, पोस्टर, विवरणिका, सजावटी विज्ञापन आदि का प्रकाशन	1310.00	710.00	600.00
2	फिल्म, वृत्तचित्र, विकास केन्द्रित सूचना पर विज्ञापनों का निर्माण तथा इलेक्ट्रॉनिक चैनलों द्वारा प्रसारण	1100.00	600.00	500.00
3	मेला, प्रदर्शनी एवं विशेष प्रचार अभियान	250.00	150.00	100.00
4	सचिवालय पुस्तकालय–सह–राज्य सूचना केन्द्र की स्थापना	40.00	40.00	0.00
5	सेमिनार, सिमपोजियम, कॉन्फ्रेंस तथा कार्यशाला	45.00	25.00	20.00
6	गीत– नाट्य	127.50	67.50	60.00
7	शोध एवं अन्वेषण योजना	1.50	1.50	0.00
8	सूचना भवन का अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण	70.00	30.00	40.00
9	विभागीय सूचना केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण एवं नेटवर्किंग	80.00	80.00	0.00
10	जनसंचार उपकरणों का क्रय	50.00	30.00	20.00
11	प्रेस क्लब की स्थापना	234.00	234.00	0.00
12	सरकारी कार्यक्रमों हेतु बाह्य स्रोत से वाहन (OB वैन)	27.00	27.00	0.00
13	सूचना भवन का निर्माण – मुख्य निर्माण कार्य	65.00	10.00	55.00
	कुल :	**3400.00**	**2005.00**	**1395.00**

वित्तीय वर्ष – 2016-17 में योजना मद में प्रस्तावित बजट उपबंध

चालू योजना

योजना उद्व्यय 6000 लाख

(रुपये लाख में)

क्र० सं०	योजना का नाम	कुल बजट उपबंध	जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना	अन्य क्षेत्रीय उपयोजना
1	फ्लैक्स, होर्डिंग, पुस्तिका (पम्पलेट्स) का निर्माण एवं प्रकाशन तथा साहित्य, मैगजीन, पोस्टर, विवरणिका, सजावटी विज्ञापन आदि का प्रकाशन	2000.00	1200.00	800.00
2	फिल्म, वृत्तचित्र, विकास केन्द्रित सूचना पर विज्ञापनों का निर्माण तथा इलेक्ट्रॉनिक चैनलों द्वारा प्रसारण	1000.00	600.00	400.00
3	मेला, प्रदर्शनी एवं विशेष प्रचार अभियान	200.00	120.00	80.00
4	सेमिनार, सिमपोजियम, कॉन्फ्रेंस तथा कार्यशाला	50.00	30.00	20.00
5	गीत–नाट्य	100.00	60.00	40.00
6	सूचना भवन का अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण	50.00	30.00	20.00
7	विभागीय सूचना केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण एवं नेटवर्किंग	100.00	100.00	0.00
8	जनसंचार उपकरणों का क्रय	50.00	30.00	20.00
9	प्रेस क्लब की स्थापना	300.00	300.00	0.00
10	सूचना भवन का निर्माण – मुख्य निर्माण कार्य	50.00	30.00	20.00
	कुल :	**3900.00**	**2500.00**	**1400.00**

नई योजनाएँ

क्र० सं०	योजना का नाम	कुल बजट उपबंध	जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना	अन्य क्षेत्रीय उपयोजना
1	झारखण्ड फिल्म विकास निगम की स्थापना एवं फिल्म निर्माताओं हेतु वित्तीय सहायता	1000.00	1000.00	0.00
2	पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना	100.00	100.00	0.00
3	सरकारी कार्यक्रमों हेतु एल.ई.डी. वाहन	1000.00	1000.00	0.00
		2100.00	**2100.00**	**0.00**

मुख्य शीर्ष – 2220 – सूचना तथा प्रचार के अन्तर्गत

वित्तीय वर्ष 2016–17 की कार्य योजना

1. **फ्लैक्स, होर्डिंग, पुस्तिका (पम्पलेट्स) का निर्माण एवं प्रकाशन तथा साहित्य, मैगजीन, पोस्टर, विवरणिका, सजावटी विज्ञापन आदि का प्रकाशन** :– वित्तीय वर्ष 2016–17 में सरकार की उपलब्धियों, कार्यक्रमों एवं नीतियों के राज्य के आम लोगों तक प्रचार–प्रसार हेतु नई होर्डिंग्स संरचना स्थापित करने, अति महत्त्वपूर्ण स्थानों पर L.E.D. स्क्रीन की संस्थापना, सजावटी विज्ञापन (Display Advertisement) तथा मुख्यालय सहित विभिन्न जिलों में अवस्थित क्षेत्रीय इकाइयों के लिए आधिकारिक डायरी, कैलेण्डर, पत्रिका विवरणी के प्रकाशन की योजना प्रस्तावित है। इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2016–17 में कुल 2000.00 लाख रुपये प्रस्तावित है, जिसमें से जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना के अन्तर्गत 1200.00 लाख तथा अन्य क्षेत्रीय उपयोजना के तहत् 800.00 लाख रुपये मात्र प्रस्तावित है।

2. **फिल्म, वृत्तचित्र, विकास केन्द्रित सूचना पर विज्ञापनों का निर्माण तथा इलेक्ट्रॉनिक चैनलों द्वारा प्रसारण** :– राज्य सरकार की उपलब्धियों एवं नीतियों के संबंध में दृश्य–श्रव्य विज्ञापन (टी०वी०स्पॉट), कल्याणकारी उपायों पर आधारित वृत्त चित्र और सरकारी योजनाओं पर आधारित विज्ञापनों का निर्माण कर उन्हें दूरदर्शन, आकाशवाणी, निजी इलेक्ट्रॉनिक, सेटेलाईट चैनल, एफ.एम. रेडियो, टी.वी. इत्यादि के माध्यम से प्रसारण की योजना है। साथ ही न्यू एज मीडिया यथा फेसबुक, लिंक्ड–इन, यू–ट्यूब ट्विटर, प्रोजेक्शन मैपिंग, मोबाइल स्कैनिंग, जियो लोकेशन सर्विस इत्यादि के माध्यम से सरकारी योजनाओं के प्रचार–प्रसार की योजना है। इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2016–17 में कुल 1000.00 लाख रुपये प्रस्तावित है, जिसमें से जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना के अन्तर्गत 600.00 लाख तथा अन्य क्षेत्रीय उपयोजना के तहत 400.00 लाख रुपया मात्र प्रस्तावित है।

3. **मेला, प्रदर्शनी एवं विशेष प्रचार अभियान** :– इस योजना का मुख्य उद्देश्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यों के प्रति आम जन में जागरुकता फैलाना है। इसके तहत् राज्य की क्षेत्रीय प्रचार इकाइयों के द्वारा विशेष अवसरों यथा–राष्ट्रीय समारोहों,

श्रावणी मेला, हिजला मेला, जगन्नाथपुर रथ यात्रा मेला आदि के अवसर पर प्रदर्शनी शिविर के माध्यम से प्रचार–प्रसार किए जाने की योजना है। साथ ही गणतंत्र दिवस एवं अन्य महत्वपूर्ण अवसरों पर झांकी के माध्यम से राज्य की कला–संस्कृति, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों आदि का प्रदर्शन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, नई दिल्ली में स्टॉल लगाना इत्यादि योजनाएँ भी प्रस्तावित हैं। इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2016–17 में कुल 200.00 लाख रुपये प्रस्तावित हैं, जिनमें से जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना के अन्तर्गत 120.00 लाख तथा अन्य क्षेत्रीय उपयोजना के तहत् 80.00 लाख रुपया मात्र प्रस्तावित है।

4. **विभागीय सूचना केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण एवं नेटवर्किंग** :– सरकारी योजनाओं/नीतियों के कार्यान्वयन हेतु सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से मुख्यालय सहित राज्य के सभी जिलों से ऑनलाईन विज्ञापन एवं प्रेस विज्ञप्ति प्राप्त की जा रही है एवं प्रेषित भी है। इस इकाई के अन्तर्गत सूचना एवं जनसंचार की नवीनतम तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। सूचना के सम्प्रेषण, ऑनलाइन विज्ञापन निर्गम, इंटरनेट लीजलाइन का अनुप्रयोग, विभागीय वेबसाइट का रख–रखाव, मुख्यमंत्री–वेबसाइट का प्रबंधन तथा SMS एकीकरण एवं संबंधित उपकरणों का क्रय इस योजना के अपरिहार्य भाग हैं।

साथ ही सूचना भवन में ई–लाइब्रेरी की स्थापना की गई है जिसके द्वारा समाचार–पत्रों की महत्वपूर्ण कतरनें ऑनलाइन ई–मेल के माध्यम से राज्य मुख्यालय से लेकर जिला तक संप्रेषित की जा रही हैं। ई–लाइब्रेरी के द्वारा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के नियमों/अधिसूचना/अनुदेश/नीतियों को संकलित कर ऑनलाइन किया गया है। साथ ही, विभिन्न विभागों से प्राप्त विज्ञापनों के प्रकाशन के उपरांत प्रकाशित सामग्रियों को ई–लाइब्रेरी के माध्यम से ई–मेल पर सुलभ कराया जा रहा है। इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2016–17 में कुल 100.00 लाख रुपये प्रस्तावित हैं, जिसमें से जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना के अन्तर्गत 100.00 लाख रुपया मात्र प्रस्तावित है।

5. **सेमिनार–सिम्पोजियम, कॉन्फ्रेंस एवं वर्कशॉप** :– सूचना एवं जनसम्पर्क से संबंधित नियमित क्षमता संवर्द्धन हेतु जनसंचार एवं विकास से संबंधित प्रमुख व्यक्तियों/संस्थानों के सहयोग से एवं उनकी विशेषज्ञता का उपयोग करते हुए विभागीय

पदाधिकारियों / कर्मचारियों, मीडिया प्रोफेशनल्स, जनसंचार के विद्यार्थियों एवं अन्य संबंधितों के लिए विभाग द्वारा राज्य एवं राज्य के बाहर (मुख्यालय राँची सहित राज्य के पाँच प्रमण्डल मुख्यालयों तथा दिल्ली सहित देश के अन्य प्रमुख स्थानों में) सेमिनार–सिम्पोजियम, वर्कशॉप, कंडक्टेड टूर के कार्यक्रम आदि आयोजित करने का प्रस्ताव है।

साथ ही सरकार द्वारा चलाये जा रहे विकास एवं कल्याणपरक कार्यक्रमों के मूल्यांकन तथा समीक्षा एवं अध्ययन हेतु शोध एवं अन्वेषण योजना वित्तीय वर्ष 2011–12 से प्रारंभ है। सरकार की विभिन्न नीतियों, विकासोन्मुखी एवं कल्याणकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से संबंधित शोध एवं अन्वेषण हेतु संदर्भ सामग्रियों का संकलन–प्रकाशन एवं विशिष्ट अकादमिक संस्थाओं के द्वारा मूल्यांकन एवं अध्ययन का कार्यक्रम प्रस्तावित है। इस हेतु संबंधित क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान अथवा अनुभव–प्राप्त व्यक्तियों / संस्थाओं को संस्थागत फेलोशिप दिये जाने का भी प्रस्ताव है।

इसके अतिरिक्त झारखण्ड के सभी वर्गों के छात्र जो कि देश के नामी संस्थानों से जन–संचार की पढ़ाई करने के इच्छुक हैं, उन्हें पाठन–शुल्क (ट्यूशन फीस) के रूप में 100 प्रतिशत सहायता अनुदान प्रदान करने का प्रस्ताव इस योजना के अंतर्गत प्रस्तावित है। यह सहायता केवल IIMC नई दिल्ली एवं धेनकनाल, जामिया मिलिया, नई दिल्ली, फिल्म एवं टेलिविजन संस्थान–पुणे, सत्यजीत रे फिल्म संस्थान, कोलकाता तथा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, दिल्ली में अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए मान्य होगी।

इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2016–17 में कुल 50.00 लाख रुपये प्रस्तावित हैं, जिनमें से जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना के अन्तर्गत 30.00 लाख तथा अन्य क्षेत्रीय उपयोजना के तहत 20.00 लाख रुपया मात्र प्रस्तावित है।

6. **गीत नाट्य** :– यह प्रचार–प्रसार का एक अत्यंत सुदृढ़, सशक्त एवं प्रभावपूर्ण माध्यम है। गीत–नाट्य में स्थानीय कलाकारों एवं स्थानीय लोक गीतों का प्रयोग किया जाता है, जिस वज़ह से स्थानीय लोग आसानी से जुड़ाव महसूस कर पाते हैं। इस योजना के तहत् मुख्यालय सहित राज्य के सभी जिलों में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में राज्य सरकार की उपलब्धियों एवं विकास कार्यक्रमों का पारम्परिक प्रचार माध्यमों से प्रचार–प्रसार किया जाता है। इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2016–17

में कुल 100 लाख रुपये प्रस्तावित हैं, जिसमें से जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना के अन्तर्गत 60.00 लाख तथा अन्य क्षेत्रीय उपयोजना के तहत 40.00 लाख रुपया मात्र प्रस्तावित है।

7. **सूचना भवन का अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण** :– राँची स्थित सूचना भवन एवं कतिपय अन्य क्षेत्रीय इकाइयों के सूचना भवनों के अनुरक्षण, मरम्मति, बाहरी दीवारों का निर्माण एवं आंतरिक सुसज्जीकरण हेतु योजना प्रस्तावित है। इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2016–17 में कुल 50.00 लाख रुपये प्रस्तावित हैं, जिसमें से जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना के अन्तर्गत 30.00 लाख तथा अन्य क्षेत्रीय उपयोजना के तहत् 20.00 लाख रुपया मात्र प्रस्तावित है।

8. **जनसंचार उपकरणों का क्रय** :– जनसंचार, विभाग का अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य है। अतएव विभाग के विभिन्न कार्यालयों में सम्प्रेषण उपकरणों की उपलब्धता अवश्यंभावी है। टी.वी. सेट, जन–संबोधन उपकरण व्यवस्था, LED, कम्प्यूटर सेट इत्यादि का क्रय इस कार्य के लिए किया जाना प्रस्तावित है। इन उपकरणों को जिला, प्रखण्ड, मुख्यालय तथा विभाग के दिल्ली स्थित कार्यालयों में प्रस्थापित किया जाएगा। इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2016–17 में कुल 50.00 लाख रुपये प्रस्तावित हैं, जिसमें से जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना के अन्तर्गत 30.00 लाख तथा अन्य क्षेत्रीय उपयोजना के तहत् 20.00 लाख रुपया मात्र प्रस्तावित है।

9. **प्रेस क्लब की स्थापना** :– राज्य के पत्रकारों/मीडिया कर्मियों के कल्याणार्थ प्रेस क्लब का निर्माण कार्य रांची में प्रारम्भ किया गया है जो वित्तीय वर्ष 2017–18 में पूर्ण हो जायेगा। विभाग द्वारा आधारभूत अवसंरचना एवं अन्य सुविधाएँ प्रदान की जाएँगी। इसके अतिरिक्त अगले वित्तीय वर्ष में धनबाद एवं देवघर में प्रेस क्लब का निर्माण किया जायेगा। इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2016–17 में कुल 300.00 लाख रुपये प्रस्तावित हैं, जिसमें से जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना के अन्तर्गत 300.00 लाख रुपया मात्र प्रस्तावित है।

10. **झारखण्ड फिल्म विकास निगम की स्थापना एवं फिल्म निर्माताओं हेतु वित्तीय सहायता** – झारखण्ड सरकार के द्वारा झारखण्ड फिल्म नीति 2015 का

गठन किया गया है। इस नीति के अंतर्गत राज्य में फिल्म स्टूडियोज, फिल्म सिटी, थियेटर एवं मल्टीप्लेक्स की स्थापना हेतु निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। विभाग के द्वारा **फिल्म विकास निधि** के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाएगी। इस फिल्म नीति में थियेटरों का पुनरुद्धार एवं महत्वपूर्ण स्थानों पर थियेटरों के लिए भूमि उपलब्ध कराना भी शामिल है। साथ ही फिल्म निर्माताओं कलाकारों तकनीकी विशेषज्ञों को प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत झारखण्ड फिल्म विकास निगम की स्थापना एवं राज्य में प्रत्येक वर्ष फिल्म महोत्सव का आयोजन भी प्रस्तावित है। इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2016–17 में कुल 1000.00 लाख रुपये प्रस्तावित हैं, जिसमें से जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना के अन्तर्गत 1000.00 लाख रुपया मात्र प्रस्तावित है।

11. **सरकारी कार्यक्रमों के लिए एल.ई.डी. वैन** – राज्य सरकार के कार्यक्रमों एवं योजना तथा मुख्यमंत्री एवं जनता के संवाद को एल.ई.डी. वैन के माध्यम से जन–जन तक पहुँचाया जाना इस योजना के अंतर्गत प्रस्तावित है। इन वाहनों के माध्यम से सरकार के विकासात्मक कार्यक्रमों को फिल्म एवं विज्ञापनों के माध्यम से राज्य के सुदूरवर्त्ती इलाकों में पहुँचाया जायेगा। सरकार के द्वारा 28 एल.ई.डी. वैन की शुरुआत कर दी गई है। इन वाहनों में जी.पी.एस. की सुविधा होती है ताकि विभाग के द्वारा मुख्यालय स्तर पर इसका अनुश्रवण किया जा सके। भविष्य में इन वाहनों के माध्यम से सीधा प्रसारण भी कराया जायेगा, ताकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सरकार एवं आमजन के बीच सीधी वार्त्ता संभव हो सके। इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2016–17 में कुल 1000.00 लाख रुपये प्रस्तावित हैं, जिसमें से जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना के अन्तर्गत 1000.00 लाख रुपया मात्र प्रस्तावित है।

12. **पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना** – राज्य सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 से राज्य के पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने की घोषणा की गई है। इस योजना के कारकों का निर्धारण अभी किया जा रहा है। इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2016–17 में कुल 100.00 लाख रुपये प्रस्तावित हैं, जिसमें से जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना के अन्तर्गत 100.00 लाख रुपया मात्र प्रस्तावित है।

आस्था विश्वास एवं श्रद्धा का केन्द्र
इटखोरी मंदिर

झारखण्ड सरकार

बदलता झारखण्ड

विकास की ओर उन्मुख झारखण्ड...

मुख्यमंत्री जन संवाद केंद्र

सिर्फ शिकायत ही नहीं...

सरकार द्वारा चलायी जा रही
विभिन्न योजनाओं की जानकारी
के लिए भी कॉल करें...

डायल करें

181

मुख्यमंत्री से जुड़ें http://cmjharkhand.in/